

# भारतवर्ष में साक्षरता के विभिन्न पहलू

मृदुला भदौरिया\*

रश्मि गोरे\*\*

साक्षरता किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं उन्नति की अनिवार्य शर्त है। संविधान के 86वें संशोधन में 6-14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य बना दिया गया तथा अप्रैल 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बना दिया गया। किंतु आज भी संपूर्ण विश्व की 35% निरक्षर जनसंख्या भारतीय है। विश्व साक्षरता औसत 84% की तुलना में भारत की साक्षरता दर मात्र 66% है। भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर में भी भिन्नता है, जहाँ केरल, मिज़ोरम, गोवा तथा हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर उच्च है, वहीं उत्तर प्रदेश, झारखण्ड एवं बिहार की दशा सोचनीय है। साक्षरता दर में यह भिन्नता मात्र राज्य स्तर पर ही नहीं है, अपितु विभिन्न समूहों में भी विद्यमान है। महिला, ग्रामीण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा निम्न आय वर्ग समूहों में साक्षरता दर अपेक्षाकृत निम्न है। महिला साक्षरता दर प्रत्येक समूह में निम्न है जिसका प्रमुख कारण समाज में व्याप्त महिला-पुरुष भेदभाव है। संतोष का विषय है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से साक्षरता दर में लैंगिक अंतर में कमी देखने में आई है।

साक्षरता एवं शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की धुरी होते हैं। भारतीय संविधान में 6-14 वर्ष तक के बालकों के लिए सार्वभौम एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करते हुए इसको राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में वरीयता दी गई है। इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 2002 में संविधान में 86वाँ संशोधन पास किया जिसके द्वारा इस आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया है। शिक्षा हेतु अधिक धन उपलब्ध कराने के लिए 2% 'शिक्षा कर' भी लगाया गया है। स्वतंत्रता के समय भारत की

\* संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर, उ.प्र.

\*\* व्याख्याता, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर, उ.प्र.

साक्षरता दर 12% थी जो वर्ष 2007 में बढ़कर 66% हो गई है। इस प्रकार 60 वर्षों में साक्षरता दर में पाँच गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है।

किंतु यह भी सत्य है कि आज भी पूरे विश्व की लगभग 35% निरक्षर जनसंख्या भारतीय है और जिस प्रकार विश्व में साक्षरता वृद्धि की प्रक्रिया देखने को मिल रही है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि 2020 तक विश्व में सबसे अधिक निरक्षरता अनुपात भारत का ही होगा। अनेक सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी भारत की साक्षरता दर में बहुत धीमी गति से वृद्धि हो रही है तथा ऐसा अनुमान है कि 'सार्वभौम साक्षरता' की प्राप्ति 2060 से पहले होना संभव नहीं होगा। अपने देश में साक्षरता के संबंध में एक दुःखद पहलू यह भी है कि पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में भी बड़ा अंतर है। सन् 2009 में प्रौढ़ साक्षरता दर पुरुषों में 76.9% जबकि महिलाओं में 54.5% मात्र थी।

साक्षरता वृद्धि हेतु सरकार ने 1988 में 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसका लक्ष्य वर्ष 2007 तक साक्षरता दर को 75% तक लाना था। इस योजना का उद्देश्य 15-35 आयु वर्ग के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना था। वर्ष 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य यह था कि 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे विद्यालय जाएँ तथा वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की विद्यालयीय शिक्षा पूरी करें। इस अभियान के महत्वपूर्ण अंग के रूप में 'शिक्षा गारंटी

योजना' तथा 'वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा' योजना को उन स्थानों के लिए अपनाया गया जहाँ तक एक किलोमीटर के दायरे में बच्चों के लिए औपचारिक विद्यालय नहीं है। इससे पूर्व वर्ष 1994 में प्रारंभ की गई डी.पी.ई.पी. योजना के अंतर्गत वर्ष 2005 तक लगभग 1,60,000 नए विद्यालय खोले गए। विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी प्राथमिक शिक्षा स्तर पर विद्यार्थियों का बीच में स्कूल छोड़ देना (Drop-out) एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। अतः विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने हेतु आकर्षित करने के लिए 1995 में बहुचर्चित 'मिड-डे मील योजना' प्रारंभ की गई।

### विश्व परिदृश्य में भारत

विश्व का साक्षरता औसत 84% है जिससे भारतवर्ष अभी काफी पीछे है। नीचे दी गई तालिका प्रौढ़ साक्षरता दर के आधार पर तुलनात्मक स्थिति प्रदर्शित कर रही है -

देश	प्रौढ़ साक्षरता दर ( 18 वर्ष + ) 2007
चीन	93.3
श्रीलंका	90.8
बर्मा	89.9
ईरान	82.4
भारत	66.0
नेपाल	56.5
पाकिस्तान	54.2
बांग्लादेश	53.5

स्रोत - एन.एफ.एच.एस.-3, 2005-06

इस प्रकार भारतवर्ष की साक्षरता दर विश्व औसत से काफी नीचे है जबकि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका एवं चीन की साक्षरता दर विश्व औसत से काफी उच्च है।

### साक्षरता - आंतरिक स्थिति

भारतवर्ष में राज्यवार भी साक्षरता की स्थिति में भिन्नता है। नीचे दी गई तालिका में जनगणना, 2001 तथा एन.एफ.एच.एस.-3 (2007) सर्वेक्षण के आधार पर राज्यवार साक्षरता की स्थिति प्रस्तुत है।

#### राज्यवार साक्षरता की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	साक्षरता दर ( % ) एन.एफ.एच.एस.-03 ( 2007 )	साक्षरता दर ( % ) जनगणना, 2001
1.	केरल	100%	90.86%
2.	मिज़ोरम	89.9%	88.80%
3.	गोवा	83.3%	82.01%
4.	हिमाचल प्रदेश	81.3%	76.48%
5.	त्रिपुरा	80.2%	73.19%
6.	महाराष्ट्र	77.6%	76.88%
7.	सिक्किम	76.6%	68.81%
8.	मध्य प्रदेश	76.5%	70.53%
9.	असम	76.3%	63.25%
10.	उत्तराखण्ड	75.7%	71.62%
11.	तमिलनाडु	74.2%	73.45%
12.	पंजाब	74%	69.65%
13.	आंध्र प्रदेश	72.5%	69.47%
14.	गुजरात	72.1%	69.14%
15.	मेंघालय	72.1%	62.56%
16.	पश्चिम बंगाल	71.6%	68.64%
17.	हरियाणा	71.4%	67.91%
18.	कर्नाटक	69.3%	66.64%
19.	ओडिशा	68.8%	63.08%
20.	राजस्थान	68%	60.71%

	भारत	67.6%	64.84%
21.	जम्मू कश्मीर	66.7%	55.52%
22.	नागालैण्ड	63.7%	60.47%
23.	छत्तीसगढ़	63.6%	64.66%
24.	अरुणाचल	62.8%	54.34%
25.	उत्तर प्रदेश	61.6%	52.67%
26.	मणिपुर	60.9%	63.74%
27.	झारखंड	58.6%	53.56%
28.	बिहार	54.1%	47.08%

स्रोत - एन.एफ.एच.एस. 2005-06, जनगणना भारत सरकार, 2001

राज्यवार स्थिति का विश्लेषण प्रकट कर रहा है कि प्रत्येक राज्य में 2001 से 2007 के मध्य साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि हुई है। किंतु केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय एवं राजस्थान की प्रगति उल्लेखनीय है। लेकिन यह चिंता का विषय है कि चार हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान पूरे भारतवर्ष के 42.76% निरक्षरता हेतु उत्तरदायी हैं।

केरल भारतवर्ष का सर्वाधिक साक्षर राज्य (90.86%) है और यहाँ का 'कोट्टायम' प्रथम वह जिला है जहाँ साक्षरता दर 100% पहुँच गई है। 1990 में एर्नाकुलम जिले में अपने कार्यक्रम 'संपूर्ण साक्षरता अभियान' की सफलता के बाद केरल सरकार ने राज्य स्तर पर यह अभियान प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत 'साक्षरता पद-यात्राएँ' तथा 'कला जत्था' का आयोजन साक्षरता हेतु सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम में सरकार ने गैर-सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया।

मिज़ोरम में 1951 में साक्षरता दर 31.14% थी जो 2001 में 88.80% पहुँच गई है। मिज़ोरम का सामाजिक ताना-बाना इस प्रकार का है जहाँ सामाजिक-आर्थिक भेद कम है। सरकार ने भी संपूर्ण साक्षरता अभियान काफ़ी मजबूती से चलाया है। सर्वप्रथम निरक्षरों की पहचान की गई और 'एनीमेटर्स' को प्रत्येक पाँच निरक्षरों को साक्षर करने का दायित्व सौंपा गया। सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना एवं विद्यालय ड्रॉप आउट हेतु विशेष योजनाओं के संचालन द्वारा साक्षरता दर में वृद्धि के विशेष प्रयास किए गए।

राजस्थान में साक्षरता की प्रगति वास्तव में प्रशंसनीय है। 1991-2001 के मध्य साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि राजस्थान में ही हुई है। सरकार द्वारा 'शिक्षा कर्मी', 'लोक-जुम्बिश' व 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' जैसी सशक्त योजनाओं का सफल संचालन किया गया। आज राजस्थान के लगभग प्रत्येक गाँव में प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस अंतराल में महिला साक्षरता दर (14.38%)

में पुरुष साक्षरता दर (11.13%) से अधिक तेज गति से वृद्धि हुई है।

सशक्त सरकारी कार्यक्रमों एवं समुदाय के सहयोग से हिमाचल प्रदेश 2001 की जनगणना में भारतवर्ष के सर्वाधिक साक्षर प्रदेशों में से एक बन गया है। वर्ष 1960 से सरकार ने विद्यालय खोलने एवं शिक्षक उपलब्ध कराने का कार्य निरंतर जारी रखा है। इस प्रदेश में भी सामाजिक आर्थिक विषमताएँ कम होने से सरकारी योजनाएँ एवं कार्यक्रम आसानी से चलाए जा रहे हैं तथा बच्चों को विद्यालय भेजना समाज में संमान की दृष्टि से देखा जाने लगा है।

जनगणना 2001 के अनुसार तमिलनाडु प्रदेश की साक्षरता दर 73.4% है जबकि 1981 में यह 54.4% ही थी। 1982 में प्रदेश में विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों हेतु मुफ्त मध्याह्न भोजन की योजना प्रारंभ की गई जिसके प्रभाव से विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। बाद में 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों से अपने सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार की योजना लागू करने का निर्देश दिया। एक ओर ऐसे राज्य हैं जहाँ साक्षरता में तेजी से वृद्धि हुई है किंतु दूसरी ओर ऐसे भी राज्य हैं जहाँ अभी प्रगति संतोषजनक नहीं है।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश ने पिछले दशक (1991-2000) में साक्षरता के स्तर में 19.14% की वृद्धि की, जिसे एक सामाजिक क्रांति कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी साक्षर बनाने का प्रयत्न किया जा

रहा है क्योंकि ये ही विद्यालय जाने वाले बच्चों के अभिभावक हैं, और इनके साक्षर होने से न केवल विद्यालय में उपस्थिति में सुधार होगा वरन् बच्चों की शिक्षा में भी गुणवत्ता आएगी। साथ ही शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। शिक्षा के लोकव्यापीकरण की संकल्पना को साकार करने के लिए राजीव गाँधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, पढ़ना-पढ़ाना आंदोलन, शिक्षा गारण्टी योजना, स्कूल चलो आदि योजनाओं का योगदान उल्लेखनीय है।

### अन्तःसमूह साक्षरता की स्थिति

भारतवर्ष में केवल राज्यवार ही साक्षरता की स्थिति में अंतर नहीं है अपितु विभिन्न समूहों—महिला-पुरुष, ग्रामीण-शहरी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदि के मध्य भी अंतर है—

#### अन्तःसमूह साक्षरता

समूह	महिला (%)	पुरुष (%)
शहरी	75	88
ग्रामीण	46	72
अनुसूचित जाति	44	72
अनुसूचित जनजाति	33	60
अन्य पिछड़ा वर्ग	52	79
निम्न आय वर्ग	19	72
मध्यम आय वर्ग	50	79
उच्च आय वर्ग	55	90

स्रोत - एन.एफ.एच.एस.-3, भारत 2005-06

इस प्रकार विभिन्न समूहों के बीच साक्षरता दर में भी अंतर गंभीर चिंता का विषय है। पिछले 30 वर्षों में महिलाओं की साक्षरता दर में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है, किंतु आज भी लगभग एक-चौथाई युवा महिला तथा एक-दहाई पुरुष निरक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष-महिला साक्षरता अनुपात में अधिक अंतर है। जहाँ शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर 88% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 75% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर 75% के मुकाबले महिला साक्षरता दर मात्र 46% है।

निरक्षरता के लिए कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कारण उत्तरदायी हैं। सुदूर बस्तियों तक सरकारी नीतियों की पहुँच का अभाव है। भारत में 30% प्राथमिक स्कूल बिना ब्लैकबोर्ड के चल रहे हैं। 80% प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त कमरे नहीं हैं। 45% प्राथमिक विद्यालय में बैठने की टाट-पट्टी पर्याप्त नहीं है। एक तिहाई विद्यालय मात्र एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। शिक्षकों को समय-समय पर अतिरिक्त कार्यों जैसे— पशुगणना, जनगणना आदि में लगा दिया जाता है। ग्रामीण साक्षरता के संदर्भ में सामाजिक कारक अधिक उत्तरदायी हैं, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में। पुरुष प्रधान मानसिकता, पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, रूढ़िवादिता आदि निरक्षरता को बढ़ावा देते हैं। प्राथमिक विद्यालयों की दूरी एवं उनमें शौचालयों की अनुपयुक्त व्यवस्था बालिका शिक्षा के मार्ग में कटक का कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक आधारभूत सुविधाओं जैसे— स्कूल

भवन, छात्रावास, यातायात सुविधा आदि का अभाव होने के साथ-साथ महिला छात्रावास, महिला अध्यापकों की कमी तथा शिक्षा संबंधी सूचनाओं का प्रसार न हो पाना आदि भी महिला शिक्षा की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

साक्षरता दर में जातिगत विषमता की स्थिति अधिक चिंताजनक है। अनुसूचित जनजाति में महिला साक्षरता दर मात्र 33% है। जनजातीय निम्न साक्षरता दर का प्रमुख कारण उनकी निम्न आर्थिक स्थिति है। जनजातीय परिवार अपने किशोर बच्चों को स्कूल भेजना श्रम विभाजन के परंपरागत स्वरूप में व्यवधान मानते हैं। दुर्गम स्थलों पर निवास, भिन्न सांस्कृतिक एवं जीवन मूल्य तथा भाषा, जनजातीय साक्षरता के मार्ग में प्रमुख समस्याएँ हैं। अधिकतर जनजातीय भाषाओं और बोलियों के अपने विकास के प्रारंभिक चरण में होने से उनका लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है। सामाजिक-आर्थिक स्तर पर साक्षरता दर में प्रबल विषमता दृष्टिगोचर हुई है। निम्न आर्थिक परिवारों में महिला साक्षरता दर पुरुष (72%) के मुकाबले मात्र 19% है, जो बहुत ही विचारणीय स्थिति है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों को कूड़ा बीनकर या स्वयं श्रम करके अपना पेट पालना पड़ता है। आजीविका पालन उनका प्रथम उद्देश्य होता है, तथा शिक्षा या स्कूल को वे गैर-ज़रूरी समझते हैं।

इस प्रकार महिला साक्षरता दर प्रत्येक समूह में पुरुषों से कम है। इसका प्रमुख कारण समाज में व्याप्त महिला-पुरुष भेदभाव ही है। साथ

ही बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाने में भी अभिभावकों में भेद-भाव देखा जाता है। यदि वे विद्यालय में प्रवेश ले भी लेती हैं तो जल्दी ही विद्यालय छोड़ भी देती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में महिला साक्षरता हाशिए पर है। (लगभग 19%) घरेलू कार्यों में संलग्नता, छोटे भाई-बहनों की देखभाल, परिवार की निर्धनता, दूर से पानी लाना, इत्यादि बीच में पढ़ाई छोड़ देने के प्रमुख कारण हैं। शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों में माँ का काम पर जाना, तथा कहीं-कहीं माँ के साथ काम पर जाना भी बालिकाओं की साक्षरता में बाधक के रूप में सामने आया है।

इसके साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक विसंगतियाँ तथा कुरीतियाँ भी लड़कियों की साक्षरता में बाधक बनती हैं। जानवरों के लिए चारा लाना, उपले बनाना, खाना बनाना, परिवार की आय के लिए योगदान देना, पर्दा प्रथा, घरेलू काम-काज में अत्यधिक व्यस्तता आदि अनेक बंदिशें महिलाओं को औपचारिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने से वंचित करती हैं।

में विद्यालय नामांकन दर में लैंगिक विषमता न सिर्फ विद्यमान है, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ इस अंतर में भी वृद्धि हुई है। भारत में राजस्थान, बिहार एवं झारखंड ऐसे राज्य हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय उपस्थिति दर में लैंगिक विषमता सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में भी स्कूल उपस्थिति दर में उच्च लैंगिक भिन्नता है। लेकिन हर्ष का विषय है कि भारत के कुछ राज्यों, जैसे— केरल, दिल्ली, सिक्किम, नागालैण्ड तथा मेघालय में बालकों की तुलना में बालिकाओं की विद्यालय उपस्थिति दर अधिक है।

साक्षर भारत के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों, नगरीय क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों) को शत-प्रतिशत विद्यालय में लाना तथा उनके द्वारा कक्षा 8 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में शत-प्रतिशत नामांकन तथा ठहराव की स्थितियाँ दयनीय हैं। उच्च आयु वर्ग में विद्यालय उपस्थिति दर की

### भिन्न आयु वर्ग में विद्यालय नामांकन दर

आवास	शहरी			ग्रामीण			
	आयु वर्ग (लिंग)	6 से 10 वर्ष (%)	11 से 14 वर्ष (%)	15 से 17 वर्ष (%)	6 से 10 वर्ष (%)	11 से 14 वर्ष (%)	15 से 17 वर्ष (%)
बालक		88	83	52	84	79	47
बालिका		88	81	51	79	66	28

स्रोत : एन.एच.एफ.एस. भारत, 2005-06

शहरी क्षेत्रों में विद्यालय नामांकन के संदर्भ में लैंगिक भिन्नता नगण्य है किंतु ग्रामीण भारत

स्थिति विशेष रूप से सोचनीय है, मुख्य रूप से बालिका शिक्षा के संदर्भ में। 15 से 17 आयु वर्ग

में बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति मात्र 17% है। बच्चों के विद्यालय से पलायन के कई कारण हैं, जिसमें अभिभावकों की नकारात्मक सोच, ग्रामीण क्षेत्र में पीढ़ी-दर-पीढ़ी निरक्षर होने के कारण बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिरुचि न होना, विद्यालयों में अध्यापक का नियमित न आना, स्वास्थ्य तथा गरीबी आदि प्रमुख हैं।

से पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूरा (PURA—Providing Urban Amenities in Rural Area-2003) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा प्रदान करायी जा रही है।

### विभिन्न आयु वर्ग में साक्षरता की स्थिति

लिंग/आयु वर्ग	15-49	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
महिला	55	74	64	55	48	43	40	38
पुरुष	78	89	84	81	76	70	69	68

स्रोत - एन.एफ.एच.एस.-3, 2005-06

विभिन्न आयु वर्ग में साक्षरता दर में उच्च लैंगिक अंतर बने हुए हैं। लेकिन प्रसन्नता का विषय है कि निम्न आयु में यह विषमता काफी कम हुई है। 45-49 आयु में साक्षरता दर में लैंगिक अंतर 30% है, जबकि 15-19 आयु वर्ग में यह अंतर मात्र 5% है। इसका प्रमुख कारण केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलायी जाने वाली प्रमुख योजनाओं जैसे- ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, मध्याह्न भोजन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जनशाला, महिला सामाख्या, लोक-जुम्बिश, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा विधेयक आदि का क्रियान्वयन प्रमुख रूप से रहा है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना (2005), विशेष आवासी विद्यालय योजना (2005) तथा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (2003) योजनाओं द्वारा आर्थिक दृष्टि

जनजातियों के सांस्कृतिक परिदृश्य, उनकी प्रतिभा और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास उल्लेखनीय है। इस कड़ी में आश्रम विद्यालय, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक योजना, राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना (2005-06), पुअरेस्ट एरिया सिविल सोसायटी आदि कार्यक्रमों द्वारा जनजातीय साक्षरता हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं।

संतोष का विषय है कि सरकार साक्षरता वृद्धि हेतु गंभीर प्रयास कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार 1996-2006 के मध्य महिलाओं के स्वास्थ्य साक्षरता एवं रहन-सहन के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जी.डी.आई. (जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स) तथा जी.इ.आई. (जेंडर



इम्प्लॉयमेंट इंडेक्स) दोनों में ही उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमें साक्षरता को एक क्रांति के रूप में देखना होगा तथा पोलियो उन्मूलन की तरह निरक्षरता को भी संक्रामक रोग समझकर उसके उपचार हेतु कई चक्रों में नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की योजना को साकार करना होगा। सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं शैक्षिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावकारी परिणामों के फलस्वरूप आशा है कि नयी जनगणना साक्षरता वृद्धि के सकारात्मक संकेत लेकर आएगी।

### संदर्भ

- गुप्ता, पी.डी., 1987, *वर्क एक्सपीरियंस क्लासेज I एण्ड II*, एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली।
- एलीमेंट्री एजुकेशन, 2006, *स्टिल ए लॉग वे टू गो - अ रिपोर्ट बाय प्रथम*, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, एलीमेंट्री।
- एजुकेशन: ई.जी.एस. एण्ड ए.आई.ई. [www.education.nic](http://www.education.nic)- अ हैंड बुक ऑन डी.ई.पी.-एस.एस.ए., 2005 इग्नू - एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया प्रोजेक्ट, इग्नू, नयी दिल्ली।
- गोविन्दा, आर. एण्ड वर्गीज, एन.ई., 1993, *क्वालिटी ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग : एन इम्पेरिकल स्टडी*, *जर्नल ऑफ एजुकेशन, प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन*, वॉल्यूम 6।
- मेहता, अरुण सी., 2002, *एजुकेशन फॉर ऑल इन इण्डिया मिथ एण्ड रियलिटी*, कनिष्क पब्लिशर्स, नयी दिल्ली।
- गोविन्दा, आर., बिस्वाल, के एवं रानी, गीता, 2006, *प्रोग्रेस ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन एक्रॉस इण्डियन स्टेट्स*, डेलिनेटिंग ड्राइवर्स ऑफ चेंज एण्ड प्रोग्रेस, नयी दिल्ली।
- मेहरोत्रा, संतोष, 2006, 'रिफॉर्मिंग एलीमेंट्री एजुकेशन इन इण्डिया : ए मेन्यु ऑफ ऑप्शन', *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट*, 26 : 261-277।
- भारत सरकार भारतीय योजना आयोग, 2005, मिड टर्म अप्रेजल ऑफ 10th फाइव ईयर प्लान (2002-2007), नयी दिल्ली।
- दयाल, मनोज, 2008, 'इम्पोरटेन्स एण्ड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन: द रोल ऑफ मीडिया', *यूनिवर्सिटी न्यूज* 46 : 28
- जैन, अंजलि, 2005, *प्राथमिक शिक्षा*, के. एस. के. पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नयी दिल्ली।
- सर्व शिक्षा अभियान, 2000, *प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल एलीमेंट्री एजुकेशन इन इण्डिया*, डिपार्टमेंट ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन एण्ड लिटरेसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- <http://www.nfhs.org>